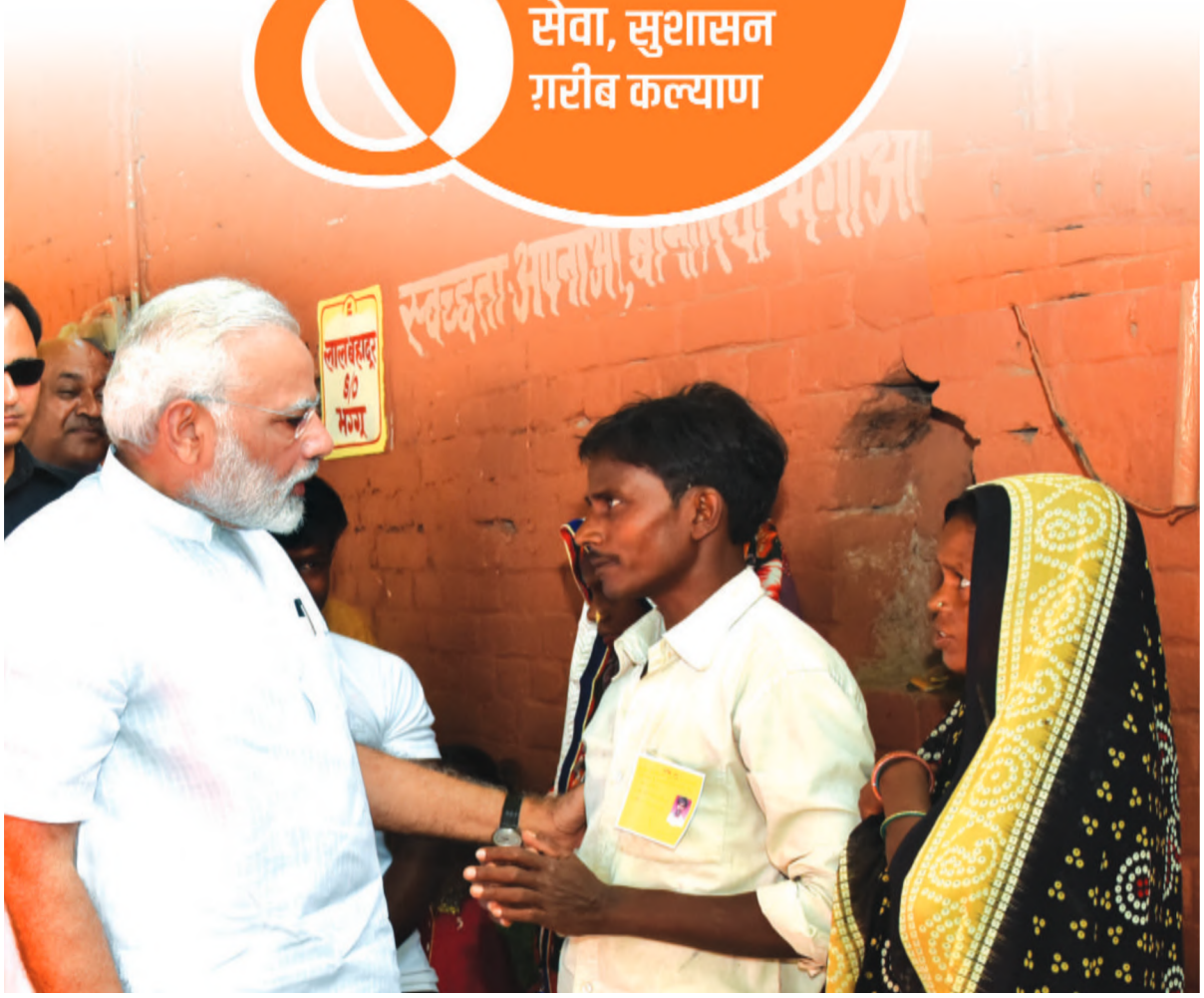
pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार

8 साल

सेवा, सुशासन
ग़रीब कल्याण



"

जिंदगी आसान रहना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसलिए इसे और आसान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है।

- नरेन्द्र मोदी

"

विषय-सूची

1. जीवन सुगमता
2. सशक्त किसान समृद्ध किसान
3. स्वास्थ्य सेवा और महामारी प्रबंधन
4. गरीब और वंचितों की सेवा
5. नए भारत के लिए नारी शक्ति
6. युवा नेतृत्व में विकास
7. अर्थव्यवस्था और सुधार
8. व्यापार सुगमता
9. बुनियादी ढांचे में गति एवं विस्तार
10. प्रौद्योगिकी- संचालित भारत
11. सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
12. पूर्वोत्तर - एक विकास इंजन
13. पर्यावरण और सतत विकास
14. राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति

जीवन सुगमता



"सरकार भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने, देश में सामाजिक जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।"
- नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

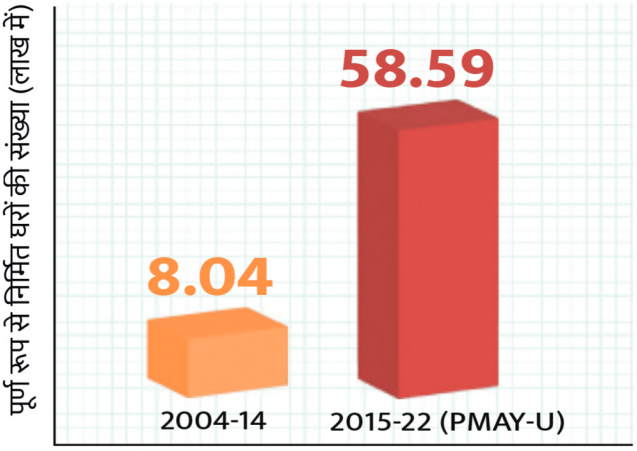
- वर्ष 2016 में शुभारंभ
- शहरी लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराए जाते हैं
- 58.59 लाख घर निर्मित/सुपुर्द किए गए
- नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर बनाए जा रहे 16 लाख घर

प्रमुख उपलब्धियां

10x	स्वीकृत मकानों की संख्या **13.48** लाख से 10 गुना बढ़कर **122.69** लाख
7.5x	पूर्ण रूप से निर्मित मकानों की संख्या **8.04** लाख से 7.5 गुना बढ़कर **58.59** लाख
22x	आवास परियोजनाओं में कुल निवेश **0.38** लाख करोड़ रुपये से 22 गुना बढ़कर **8.31** लाख करोड़ रुपये
10x	आवास के लिए केंद्रीय सहायता **0.20** लाख करोड़ रुपये से 10 गुना बढ़कर **1.86** लाख करोड़ रुपये

*2004-14 बनाम 2015-22

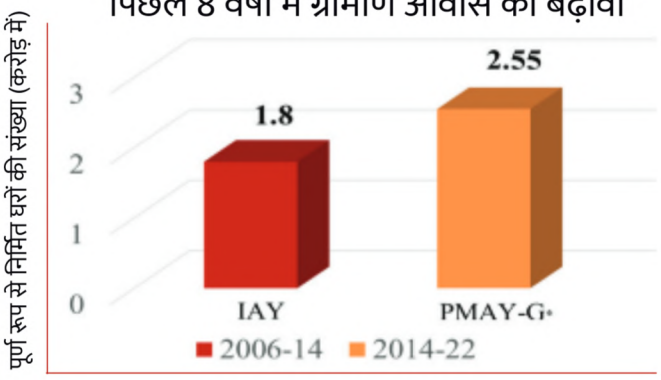
शहरी आवास को बढ़ावा



प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- वर्ष 2016 में शुभारंभ
- ग्रामीण लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाते हैं
- 2.55 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा

पिछले 8 वर्षों में ग्रामीण आवास को बढ़ावा





घर का आकार 20 वर्ग मीटर (आईएवाई) से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर (पीएमएजी-वाई) करना



यूनिट सहायता 70/75 हजार रुपये (आईएवाई) से बढ़ा कर 1.20/1.30 लाख रुपये (पीएमएजी-वाई)



स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

- शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और शहरी ठोस अपशिष्ट का शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य
- 20 करोड़ से अधिक नागरिक सीधे तौर पर जुड़े; 66.9 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6.42 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
- 4,371 शहर व कस्बे खुले में शौच से मुक्त घोषित

- ‘कचरा मुक्त शहर’ बनाने की दृष्टि से 1 अक्टूबर, 2021 को ‘एसबीएम 2.0’ का शुभारंभ



स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

- 2014 में 39% स्वच्छता कवरेज; 2022 में एसबीएम के अंतर्गत स्वच्छता कवरेज बढ़कर शत-प्रतिशत
- 11 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों; 2,03,970 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण

- 75,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया
- 'दस का दम' के तहत 12 लाख गतिविधियों में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा



अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

- जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराकर लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने का लक्ष्य

- 12.7 करोड़ नए नल कनेक्शन प्रदान किए गए; 95 लाख नए सीवरेज कनेक्शन दिए गए
- 2,360 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवरेज शोधन संयंत्र जोड़े गए
- 350 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और लगभग 4100 हेक्टेयर हरित क्षेत्र एवं पार्क विकसित किए गए
- शहर में जल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2021 को 'अमृत 2.0' का शुभारंभ

हर घर जल

- अगस्त 2019 में शुभारंभ, जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराना
- पानी समितियां; जन आंदोलन; समुदाय का स्वामित्व और महिलाओं की केंद्रीय भूमिका



2019 से पहले **3.23** करोड़ परिवारों को नल से जल आपूर्ति की सुविधा थी

पिछले 3 वर्षों में **6.29** करोड़ नए परिवारों को दिया गया नल से पानी का कनेक्शन

सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)

25 सितंबर, 2017 को घोषित

ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का उद्देश्य

अक्टूबर 2017 तक: 89 प्रतिशत घर विद्युतीकृत

लॉन्च के बाद से 31 मार्च 2021 तक **2.82 करोड़** घरों को विद्युतीकृत किया गया

2022: **99.99** प्रतिशत घर विद्युतीकृत

8 साल
सेवा, सुशासन
गरीब कल्याण

सशक्त किसान समृद्ध भारत





"कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गांवों के आर्थिक कौशल देश की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करते हैं।"

- नरेन्द्र मोदी

पीएम किसान

- 2019 में लॉन्च, किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये
- पहली बार पूरे देश में शुरू किया गया प्रत्यक्ष नकद समर्थन
- पी एम किसान योजना के अंतर्गत 11.78 करोड़ लाभार्थी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

- 2016 में लॉन्च की गई; फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता
- 37.52 करोड़ किसानों का पंजीकरण, पिछले 6 वर्षों में 10.25 करोड़ से अधिक आवेदकों को 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावे हुए प्राप्त
- पंजीकृत किसानों में 80 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान

फसल बीमा योजना 2014-15 बनाम 2021-22

बीमित आवेदनों में 2.5 गुना वृद्धि	गैर ऋण वाले किसानों के हिस्से में 7 गुना वृद्धि	प्रति हेक्टेयर औसत बीमा राशि में 2.5 गुना वृद्धि
3.70 करोड़ से बढ़कर 8.2 करोड़	5.4 प्रतिशत से बढ़कर 35.5 प्रतिशत तक	18,000 रुपये से बढ़कर 45,000 रुपये

ई-नाम: मौजूदा बाजारों को ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत करने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया



एमएसपी में गुणात्मक वृद्धि

खाद्यान्न	एमएसपी (2014-15) (रुपये/क्विंटल)	एमएसपी(2021-22) (रुपये/क्विंटल)	% परिवर्तन
चावल	1360	1940	**43**
गेहूँ	1450	2015	**39**

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- पोषक तत्वों के उपयोग में वृद्धि के लिए 2014-15 में योजना की शुरुआत
- किसानों को लगभग 23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किए गए जारी

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

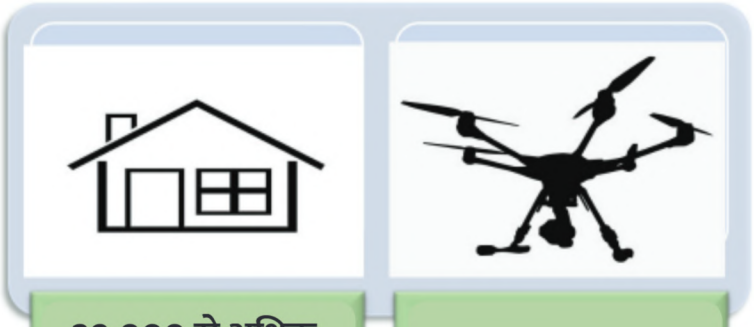
- एक विशेष अभियान के तहत सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी के माध्यम से कवर किया जाएगा
- 3.4 लाख करोड़ रुपये की ऋण-सुविधा के साथ 3 करोड़ से अधिक नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किये गए

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

- उद्देश्य - ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत के स्तर पर जल उपयोग में दक्षता बढ़ाना
- 2015-16 से 63.96 लाख हेक्टेयर कवर; अब तक लगभग 57.5 लाख किसान हुए लाभान्वित
- नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया
- 2021-22 के बजट में कोष की राशि बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये की गयी

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्र बनाना)

- अप्रैल 2020 में किया गया लॉन्च
- ग्रामीण इलाकों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित करने का उद्देश्य



29,000 से अधिक गाँवों में **36 लाख** संपत्ति कार्ड/ मालिकाना दस्तावेज किए गए जारी (31 मार्च, 2022 तक)

1.35 लाख गाँवों का ड्रोन सर्वे हुआ पूरा (01 मई, 2022 तक)

स्वास्थ्य सेवा और महामारी प्रबंधन



"आयुष्मान भारत का यह पहला साल संकल्प, समर्पण और सीखने की प्रक्रिया का समय रहा है। यह भारत की संकल्प शक्ति है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना भारत में सफलतापूर्वक चला रहे हैं।"

- नरेन्द्र मोदी

आयुष्मान भारत

विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना



पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन

- 25 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन की सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना
- वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि में 64,180 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (पीएम-एबीडीएम)

- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 27 सितंबर 2021 को किया गया शुभारंभ
- 22 करोड़ से अधिक आभा (एबीएचए) नंबर और 15 हजार स्वास्थ्यकर्मी पंजीकृत
- 64,700 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं (सरकारी या निजी क्षेत्र के अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों, क्लीनिकों आदि सहित) शामिल

ई-संजीवनी ओपीडी

- 73 लाख से अधिक ई-संजीवनी ओपीडी परामर्श दिए गए

- **आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एबी-एचडब्ल्यूसी)**

1.18 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित

53 करोड़ लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच

2.34 करोड़ टेली परामर्श किए गए आयोजित



अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार



मेडिकल कॉलेज

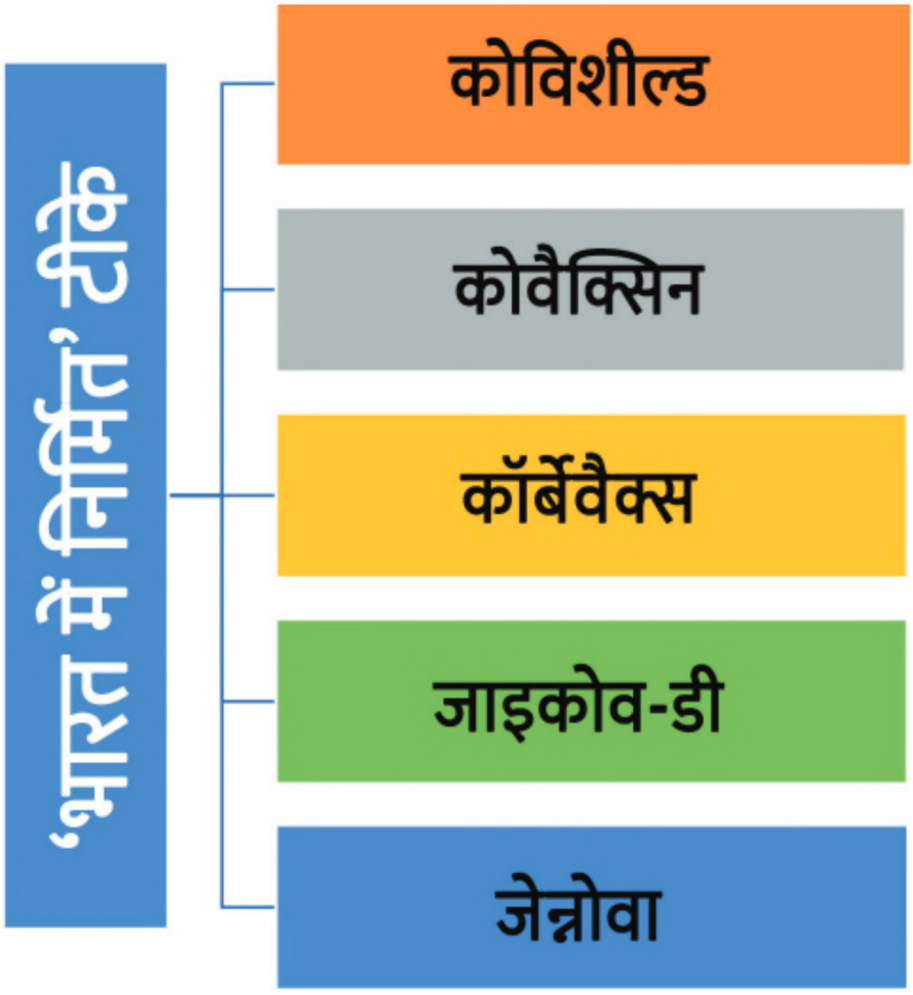


कोविड-19 टीकाकरण अभियान

- टीके की 190 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
- को-विन ने अब तक 100 करोड़ से अधिक अनंतिम, 87.6 करोड़ अंतिम और 3 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक के जारी किए हैं प्रमाण-पत्र
- दुर्गम इलाकों में कोविड-19 के टीकों की ड्रोन आधारित आपूर्ति शुरू



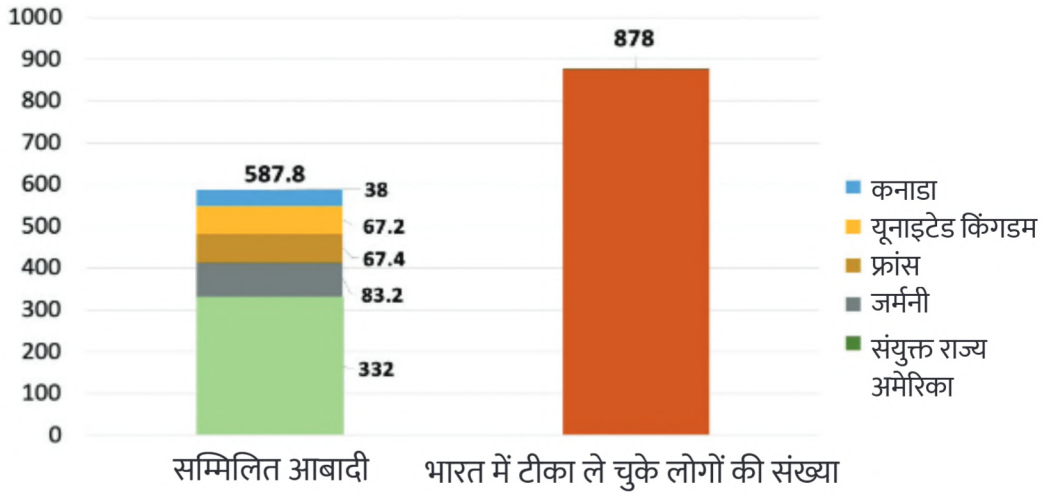
विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान



कोविड प्रबंधन

- फोकस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग' के साथ समय पर जांच, निगरानी एवं उपचार, 'कंटेनमेंट जोन', सामुदायिक निगरानी, घर में अलग रहने संबंधी प्रोटोकॉल और प्रभावी नैदानिक उपचार
- मई 2022 तक कोविड-19 की जांच के लिए लगभग 4000 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क
- 'मेक इन इंडिया दृष्टिकोण' के तहत स्वदेशी उद्योग को सुविधा प्रदान कर महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता में कमी
- रोग की निगरानी और हॉटस्पॉट की पहचान करने के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स, दवाओं के वितरण, चिकित्सीय ऑक्सीजन और टीकों की निगरानी के लिए आईटी प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग

भारत में टीका ले चुके लोगों की आबादी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा की सम्मिलित कुल आबादी से अधिक है



बाल स्वास्थ्य एवं पोषण

मिशन इन्द्रधनुष

- मिशन इंद्रधनुष (एमआई) टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाकर बच्चों का पूर्ण टीकाकरण तथा गर्भवती महिलाओं के बीच इस कवरेज को 90% करने और उसके बाद इसे निरंतर बनाए रखने के लिए

- 4 मई 2022 तक 4.31 करोड़ बच्चों और 1.08 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण
- आईएमआई 4.0 आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) वाले जिलों सहित 416 जिलों में चल रहा है



गरीब और वंचितों की सेवा

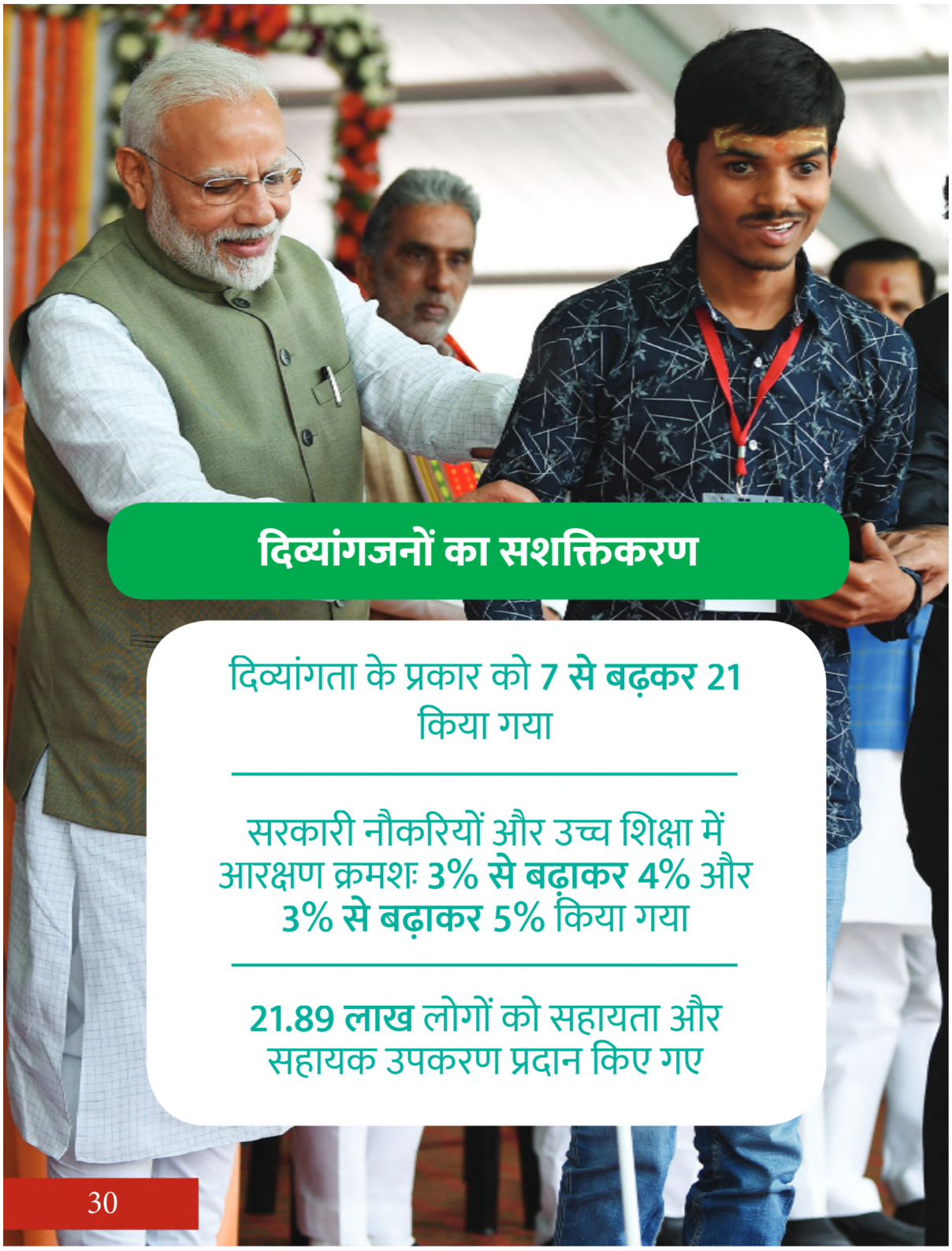


"अंत्योदय के सिद्धांत से निर्देशित, हमारी सरकार गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और पीछे छूट गए लोगों के प्रति समर्पित है"

- नरेन्द्र मोदी

गरीब कल्याण, देश का कल्याण

- गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
- 80 करोड़ भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
- वित्तीय समावेशन की विश्व में सबसे बड़ी पहल
- कमजोर वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति और उनके अधिकारों की रक्षा
- दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण
- जनजातीय लोगों के लिए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना



दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण

दिव्यांगता के प्रकार को **7 से बढ़कर 21** किया गया

सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण क्रमशः **3% से बढ़ाकर 4%** और **3% से बढ़ाकर 5%** किया गया

21.89 लाख लोगों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए गए

जनजातीय लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित

15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया

384 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को शुरू किया गया

3,110 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना; 8.5 लाख कारीगरों, शिल्पकारों और खान-पान विशेषज्ञों को रोजगार



कमजोर वर्ग

आकांक्षाओं की पूर्ति

- ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण
- राज्यों को खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार

अधिकारों की रक्षा

एससी और एसटी की न्याय प्राप्ति को मिली मजबूती

तीन तलाक की प्रथा खत्म

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

पीएम स्वनिधि - रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए आसान ऋण

- कोविड-19 महामारी के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों को गिरवी मुक्त कर्ज की सुविधा दी गई
- पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 31.9 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को मिला ऋण



80 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित



दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल

45 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम जन धन योजना के तहत औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया गया

लाभार्थियों के बैंक खातों में **22 लाख करोड़** रुपये से ज्यादा का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, **2.22 लाख करोड़** रुपये की अनुमानित बचत

नए भारत के लिए नारी शक्ति

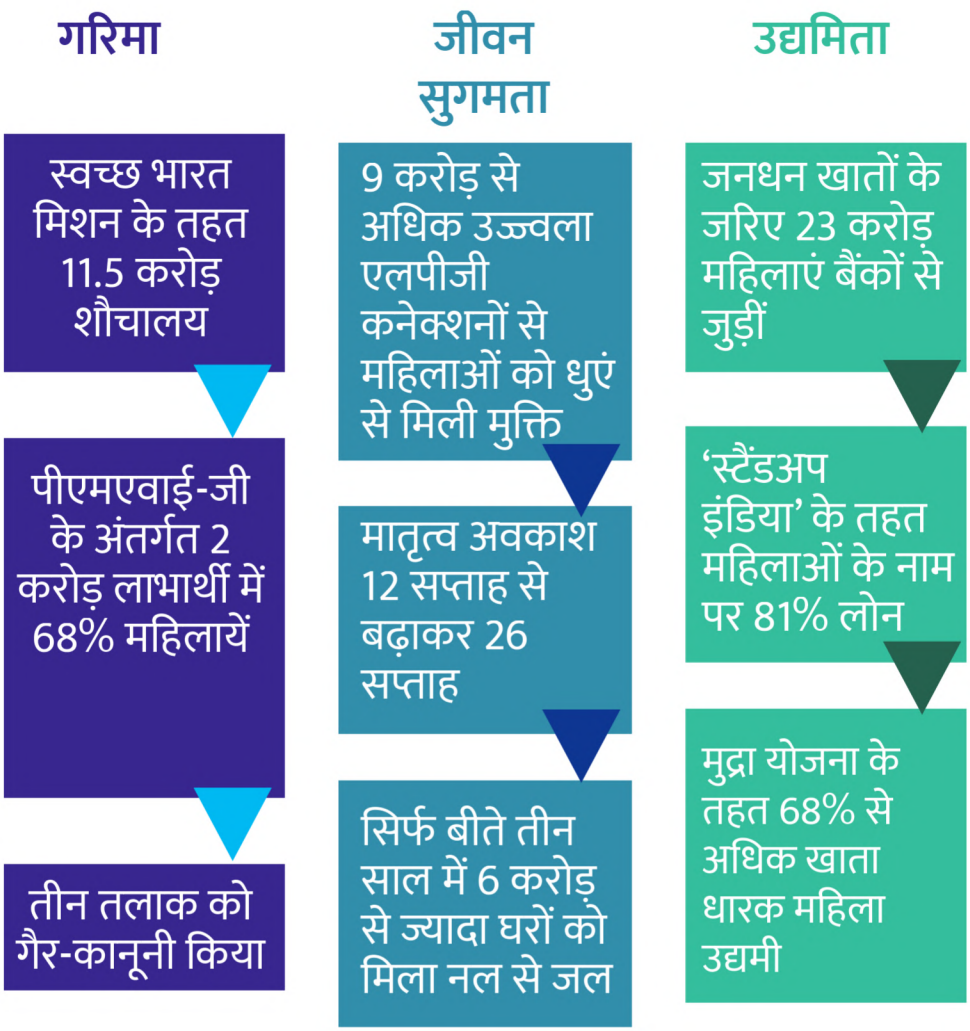
प्रगति को गति देने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य

"महिला सशक्तिकरण भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उन्हें राष्ट्र निर्माताओं के रूप में देखते हैं।"

- नरेन्द्र मोदी



महिलाओं के जीवन में सुधार



उज्ज्वला योजना

2014	2021
16.62 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन	**28.29 करोड़** घरों में एलपीजी कनेक्शन



तब

अब

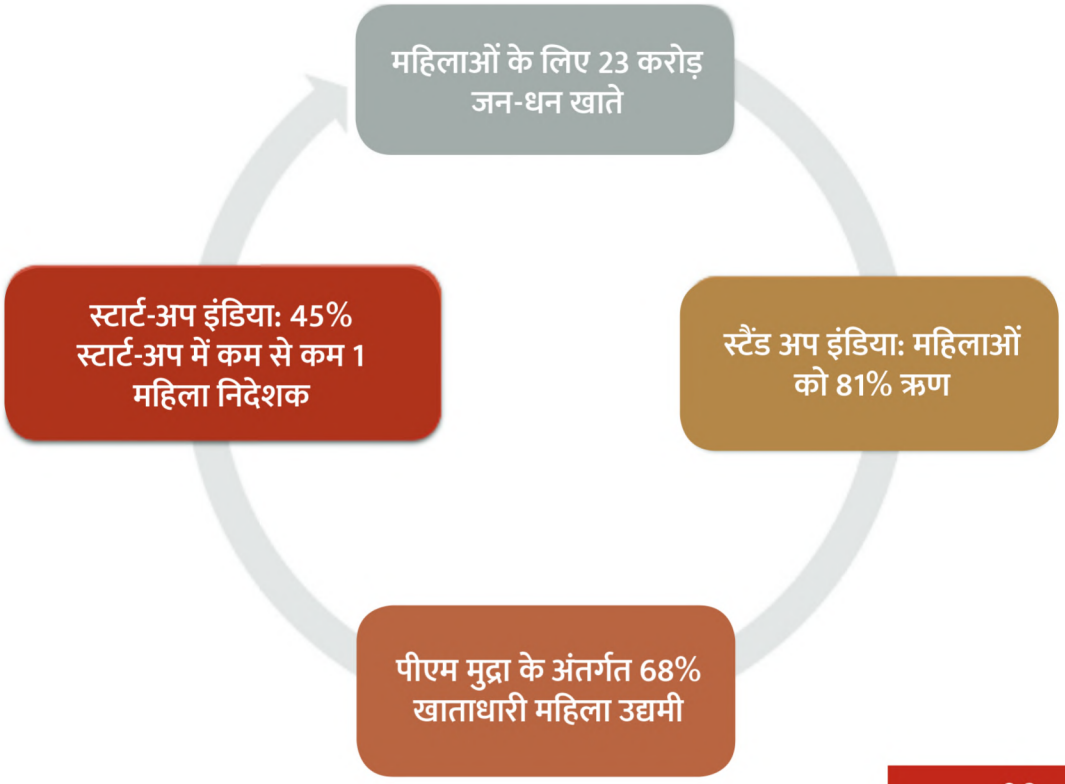


सख्त कानून

तीन तलाक

- मुस्लिम महिला की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित
- तीन तलाक के मामलों में 82% की कमी

प्रधानमंत्री जन-धन योजना



महिलाओं का जीवन बना आसान

- 2019 में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास था नल कनेक्शन
- जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 वर्षों में 6.29 करोड़ नये परिवारों को मिला नल से जल

महिला हेल्पलाइन

- 1 अप्रैल 2015 को महिला हेल्पलाइन 181 शुरू की गई जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल के जरिए 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करती है

181

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

- 2.78 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का नामांकन; मई 2022 तक पीएमएमवीवाई के तहत 2.47 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 10,793.34 करोड़ रुपये वितरित



युवा नेतृत्व में विकास



"हमारे युवा आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव बनेंगे"

- नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

परिवर्तनकारी सुधार: 1986 की 34 साल पुरानी एनईपी को बदला



स्किल इंडिया मिशन:

पीएम कौशल विकास योजना

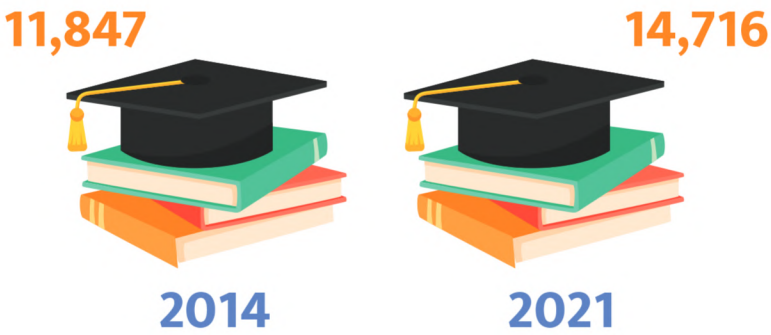
युवाओं को **नि:शुल्क** कौशल प्रशिक्षण

1.34 करोड़ युवा प्रशिक्षित (21 अप्रैल तक)

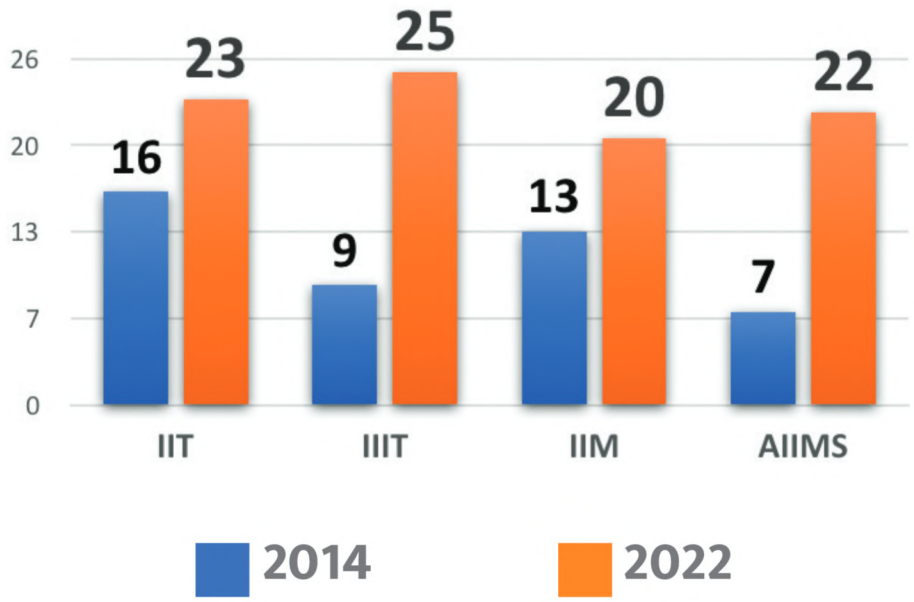
पहले की लर्निंग को मान्यता

50 लाख से ज्यादा व्यक्तियों का किया गया अपस्किल और रीस्किल

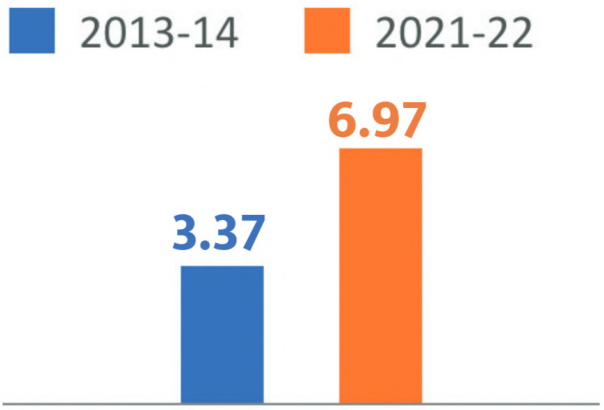
औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आईटीआई) में 24% की बढ़ोतरी



शिक्षा का बुनियादी ढांचा

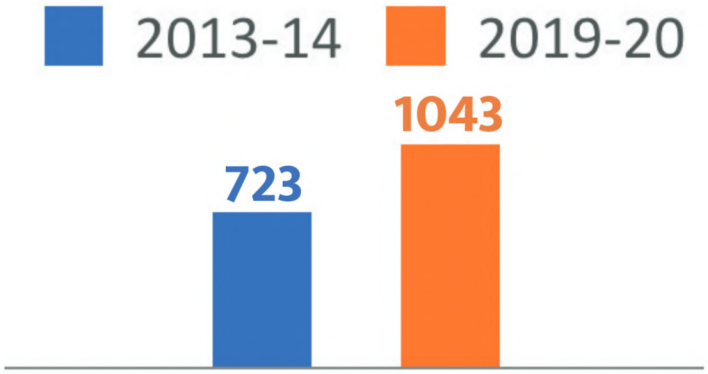


2013-14 के बाद से कुल खर्च हुआ दोगुना



(शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त व्यय)
(लाख करोड़ में)

2014 के बाद से जोड़े गए लगभग 320 विश्वविद्यालय



(विश्वविद्यालयों की संख्या)

वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा

26 अप्रैल 2022 तक देश में अटल टिंकरिंग लैबों की संख्या **9,500** से अधिक

साथ ही ये 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 722 जिलों में हैं फैले हुए



भारत सीड फंड के जरिए, 300 इन्क्यूबेटरों से 3,600 उद्यमियों को प्रदान की गई सहायता

खेलो इंडिया

इसे देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए अप्रैल 2016 में शुरू किया गया

देश में खेलों का बुनियादी ढांचा

2008-14	38
2020-21	360


एक भारत
श्रेष्ठ भारत
के साथ भारत अनेकता में एकता को मना रहा है
31 अक्तूबर 2015 को शुभारंभ
देश भर में विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच समुदायों, धर्मों, संस्कृतियों और जातियों के विविध समूहों के बीच एकजुटता की भावना को प्रज्वलित करना इसका उद्देश्य है।


ईबीएसबी के अंतर्गत गतिविधियां
भोजन उत्सव/ पाककला विनियमन
सांस्कृतिक विनियमन
युवा उत्सव
ईबीएसबी दिन/ ईबीएसबी क्लब
शैक्षिक विनियमन
खेल की स्पर्धा
पर्यटन विनियमन
पुस्तकों का अनुवाद
भाषाओं को सीखना
युग्मित राज्य गतिविधियाँ
ऑनलाइन बातचीत

अर्थव्यवस्था और सुधार



"जीएसटी ने सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाया है। जीएसटी का समर्थन करने के लिए पूरा देश साथ आया है और प्रौद्योगिकी से भी मदद मिली है।"

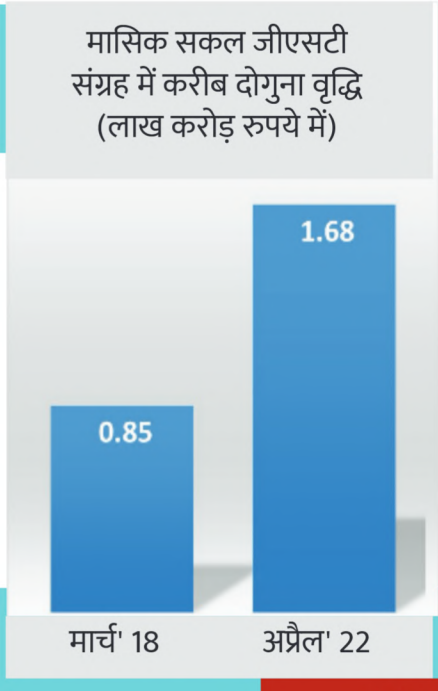
- नरेन्द्र मोदी

वैश्विक महामारी के बावजूद सबसे तेज वृद्धि

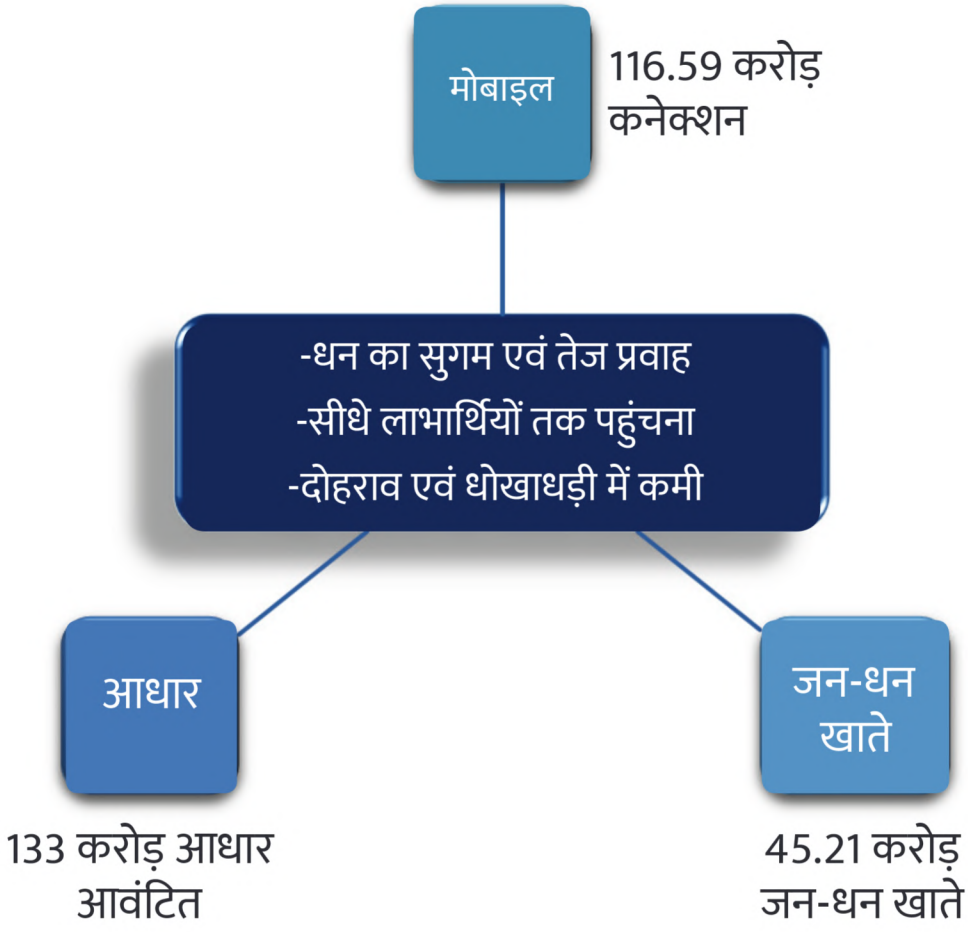
- वर्ष 2022 में 8.2 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर के साथ भारत के लिए मजबूत विकास संभावनाएं, जो भारत की दुनिया में सबसे तेजी से उभरती एक प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रही है
- अप्रैल 2022 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार 2022 और 2023 के लिए वैश्विक विकास दर केवल 3.6 प्रतिशत अनुमानित
- निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि और खपत में उछाल के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान आर्थिक गतिविधियों में सुधार

जीएसटी: एक राष्ट्र, एक कर

1 जुलाई, 2017 को लॉन्च: जीएसटी में 17 प्रमुख करों और 13 उपकरों को शामिल करते हुए पूरे भारत को एक बाजार में तब्दील किया गया। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये पर अब तक का सर्वाधिक रहा



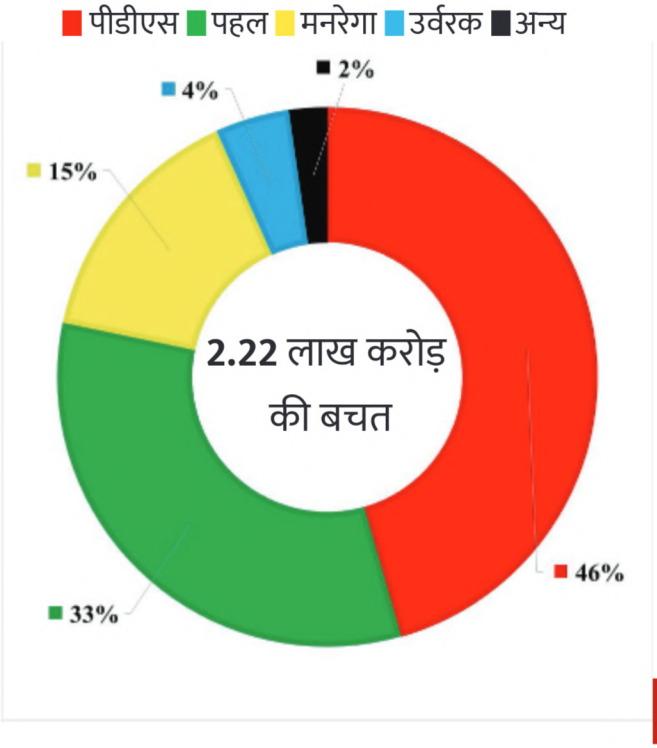
आधार-डीबीटी लिंकेज- नागरिकों का सशक्तिकरण, शासन में सुधार



डीबीटी: लीकेज़ को हटाया

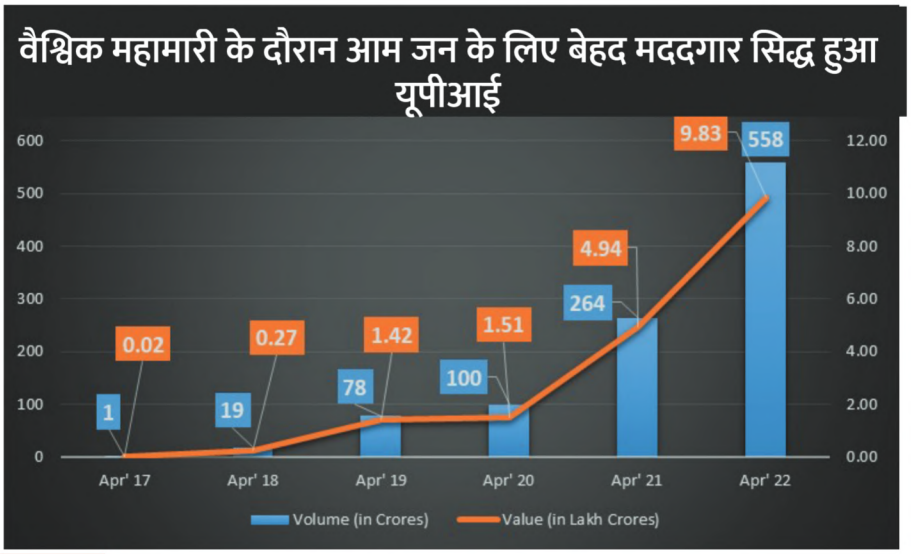
- 3.99 करोड़ नकली एवं जाली राशन कार्ड (2013-2020) को हटाया
- 4.11 करोड़ जाली/ फर्जी/ निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन समाप्त किये
- ग्रामीण विकास मंत्रालय में जाली/ फर्जी/ अपात्र लाभार्थियों को हटाया

अनुमानित बचत



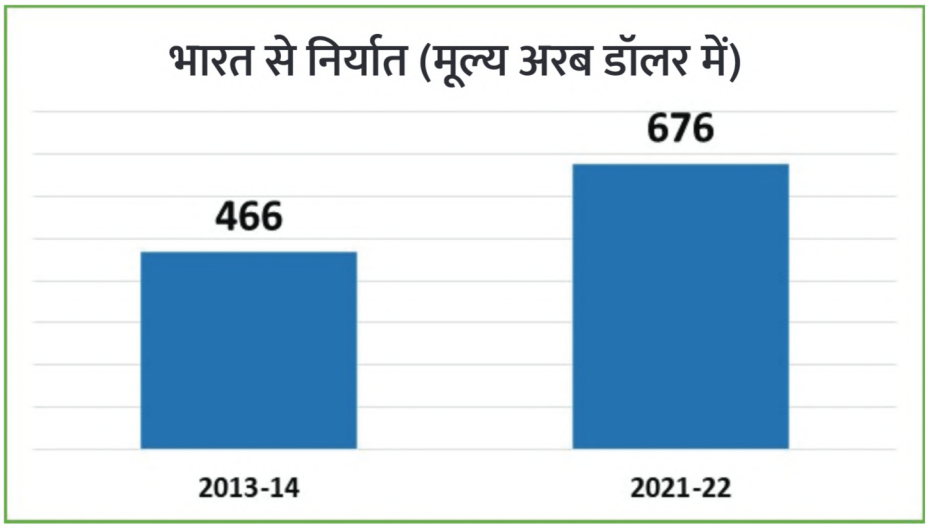
यूपीआई: देश का सबसे बड़ा एकल खुदरा भुगतान प्लेटफॉर्म

- 2016 में लॉन्च
- छोटे मूल्य के लेन-देन को बढ़ावा
- 600 करोड़ लेन-देन के जरिये लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन
- 26 करोड़ से अधिक यूपीआई उपयोगकर्ता, 15 करोड़ से अधिक यूपीआई क्यूआर कोड जारी
- कुल डिजिटल लेन-देन में 40 प्रतिशत योगदान



निर्यात: लोकल का ग्लोबल रुख

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कुल निर्यात 676.2 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा जो पिछले वर्ष के मुकाबले 34.5 प्रतिशत अधिक है



- वित्त वर्ष 2021-22 में मर्चेंडाइज निर्यात 419.65 अरब डॉलर पर अब-तक का सर्वाधिक रहा। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई
- सेवाओं का निर्यात पहली बार 254.4 अरब डॉलर रहा जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 21 प्रतिशत अधिक है
- भारत के कृषि निर्यात ने 50 अरब डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर को हासिल किया

एमएसएमई क्षेत्र के लिए सुधार

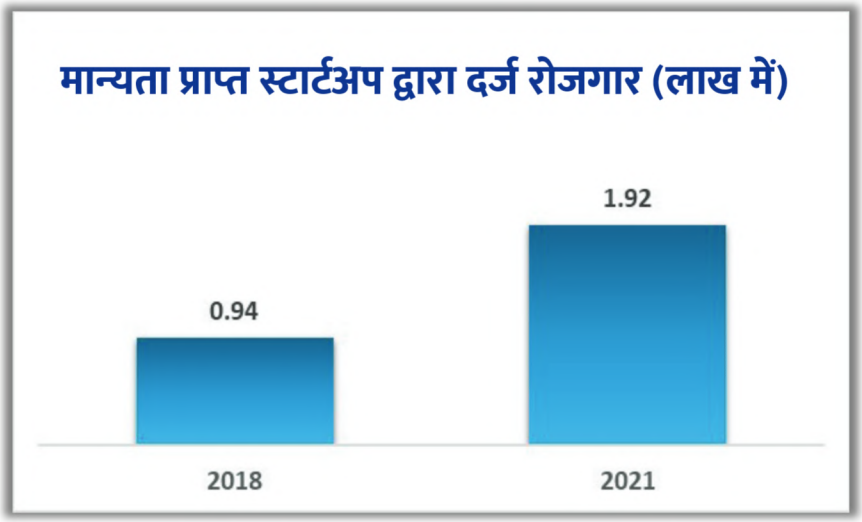
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: हाशिए पर मौजूद/सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन



- गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण
- जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए

स्टार्टअप इंडिया:

- भारत में 2 मई 2022 को 100वां यूनिकॉर्न बना
- वैश्विक स्तर पर हर 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत में
- सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 647 भारतीय जिलों में स्टार्टअप को मान्यता दी गई
- 7 लाख से अधिक रोजगार का सृजन (2018 से 2021 तक)

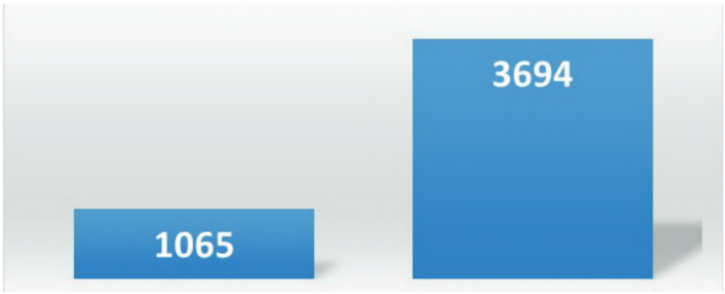


प्रधानमंत्री जन-धन योजना: विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल

सबको बैंकिंग, सबको सुरक्षा और सबको वित्त पोषण

- 15 अगस्त 2014 को लॉन्च
- 31.64 करोड़ रुपे कार्ड जारी
- औसत जमा राशि 3,694 रुपये
- कुल 1.66 लाख करोड़ रुपये जमा

औसत जमा (रुपये में)



बैंक खाते: 2015 तक 107 करोड़, पीएम जेडीवाई के तहत 45 करोड़ खाते खुले

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं	प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पहली बार जीरो बैलेंस अकाउंट्स खोले गए

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस:

- समावेशन, उपयोगिता, पारदर्शिता, दक्षता और लागत में बचत
- पोर्टल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक खरीद दर्ज की
- चालू वित्त वर्ष के दौरान ऑर्डरों की संख्या 22 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 31.5 लाख के पार

व्यापार सुगमता

"हम सभी वैश्विक कंपनियों के यहां आने और भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का स्वागत करते हैं। दुनिया में ऐसे कुछ ही देश होंगे जो आज भारत की तरह अवसर पेश कर रहा हो।"

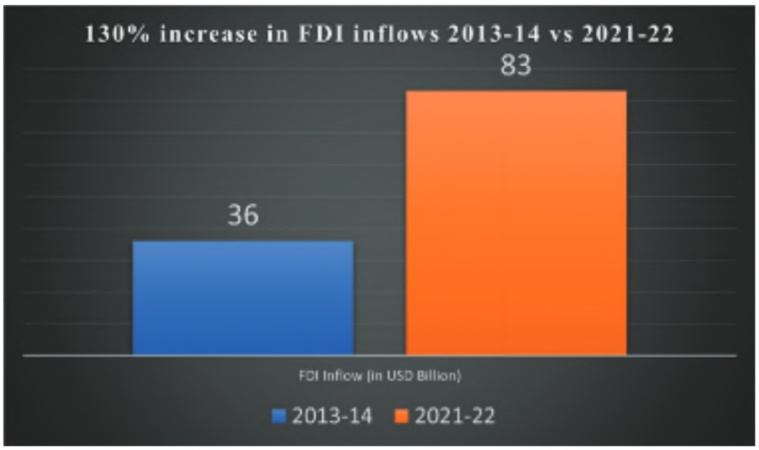
- नरेन्द्र मोदी



देश में कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान हरसंभव प्रयास किए हैं। अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने और पारदर्शिता पर जोर देने के साथ ही विभिन्न कानूनों एवं विनियमों के सरलीकरण से उल्लेखनीय बदलाव आया है।

- **कानूनों के बोझ से मुक्ति:** 2007 व्यापार संबंधी कानून अथवा बाधाओं को समाप्त कर दिया गया। 25,000 अनुपालन समाप्त कर दिए गए
- **कंपनी कानून का गैर-अपराधीकरण:** 2017 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया और कई प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत बना दिया गया और नागरिक त्रुटियों के रूप में माना गया
- **कंपनियों पर कर का बोझ घटा:** घरेलू कंपनियों के लिए अधिभार सहित प्रत्यक्ष कर को 30 प्रतिशत से घटाकर अधिभार और उपकर सहित 25.17 प्रतिशत कर दिया गया

एफडीआई अंतर्वाह (अरब डॉलर में)





नीतिगत सुधार

- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2020
- एफडीआई निवेश को बढ़ावा
- भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) को लागू करना



औद्योगिक गलियारा

- भारत में नए औद्योगिक नोड्स का विकास
- 11 औद्योगिक गलियारे का विकास



पीएलआई योजना

- भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना
- अगले 5 साल के दौरान 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता
- 60 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य



- **नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस)** को निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया है। इसके जरिए वे 32 केंद्रीय विभागों और 16 राज्यों से विभिन्न मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बुनियादी ढांचे में गति एवं विस्तार



"बुनियादी ढांचा सीमेंट और कंक्रीट से कहीं अधिक है। बुनियादी ढांचा बेहतर भविष्य की गारंटी देता है। बुनियादी ढांचा लोगों को आपस में जोड़ता है।"

- नरेन्द्र मोदी

पीएम गतिशक्ति- प्रगति को रफ्तार

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी
- नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुगमता
- वस्तु एवं सेवाओं की आवाजाही में लागत और समय की बचत
- बुनियादी ढांचे के विकास के साथ रोजगार सृजन

सड़क, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग, बंदरगाहों का विस्तार

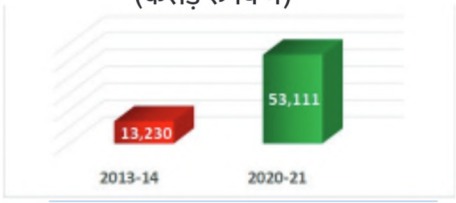
कनेक्टेड भारत का निर्माण

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (किलोमीटर में)

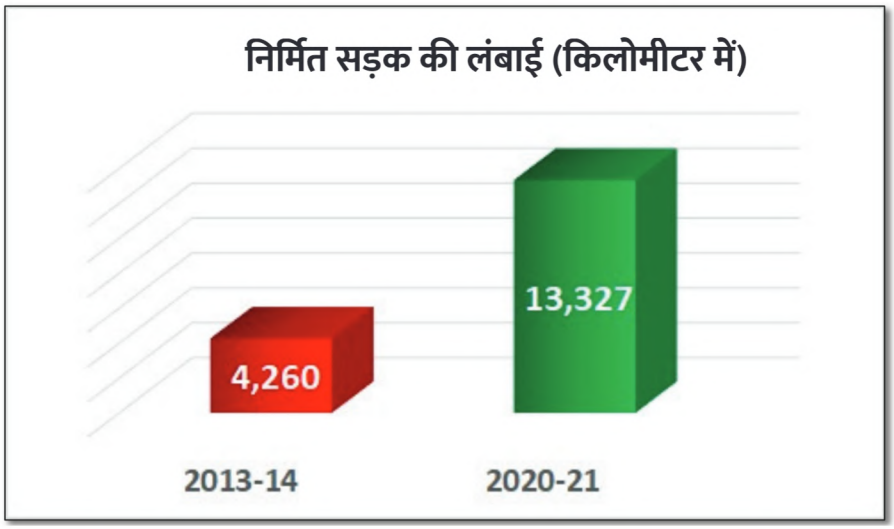


2013-14 से 2020-2021 के दौरान 1.5 गुना वृद्धि

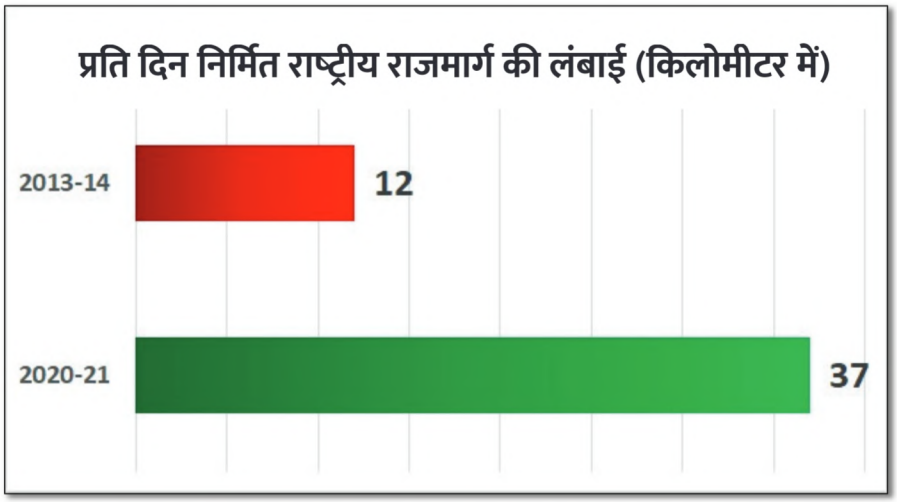
सड़क एवं पुल के निर्माण पर पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपये में)



2013-14 से 2020-2021 के दौरान 4 गुना वृद्धि



2013-14 से 2020-2021 के दौरान 3 गुना वृद्धि

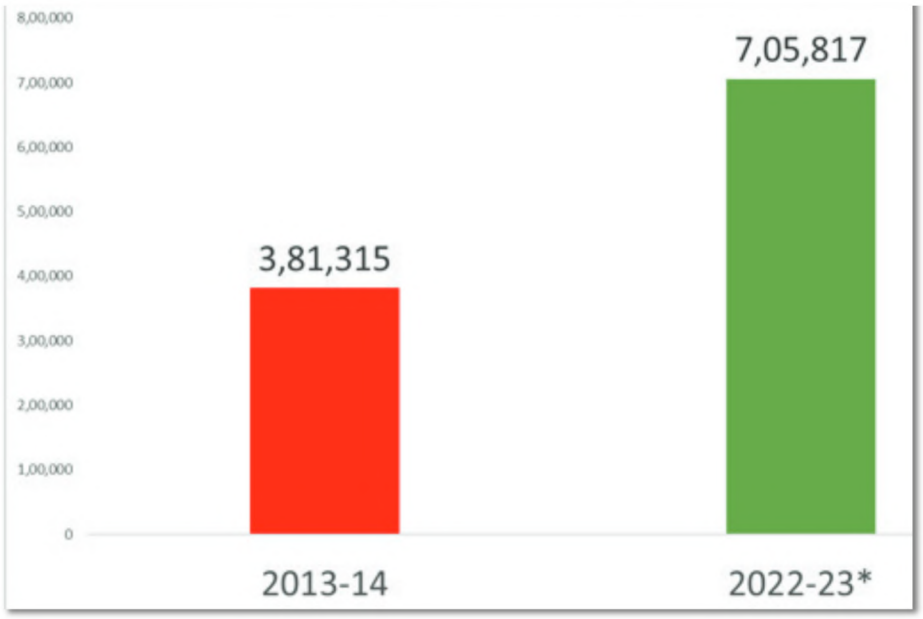


2013-14 से 2020-2021 के दौरान निर्माण की गति में 3 गुना वृद्धि

अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

निर्मित सड़क (किलोमीटर में)

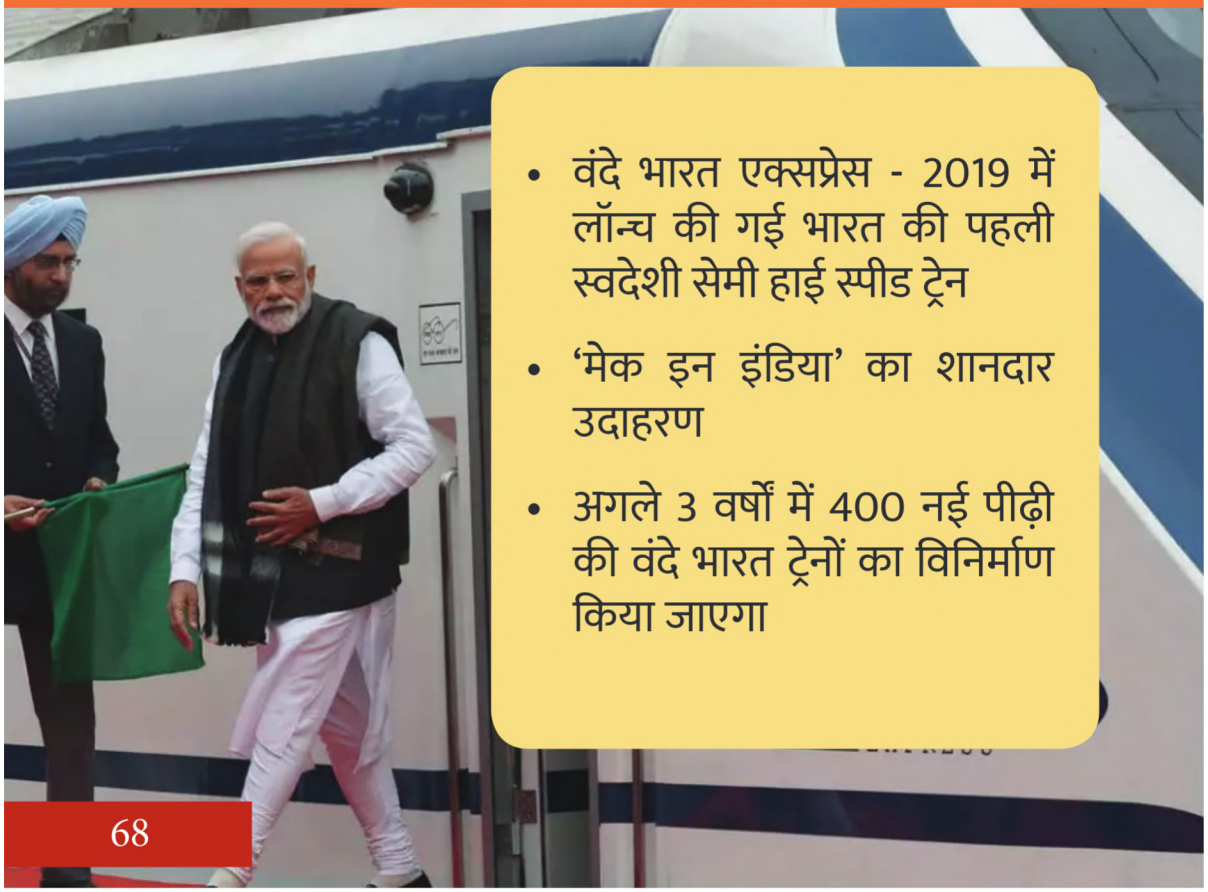


परिवहन परिवेश में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

फास्टैग ई-टोलिंग

728 राष्ट्रीय और 201 राज्य राजमार्ग शुल्क प्लाजा अब फास्टैग से जुड़े

रेलवे में प्रमुख उपलब्धियां



- वंदे भारत एक्सप्रेस - 2019 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन
- 'मेक इन इंडिया' का शानदार उदाहरण
- अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण किया जाएगा



मेट्रो रेल में 'मेक इन इंडिया'



- 2014: 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का परिचालन
- 2022: 18 शहरों में 791 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का परिचालन, 27 शहरों तक पहुंची मेट्रो

विमानन में प्रमुख उपलब्धियां

2014	2021
• 400 विमान • 74 हवाई अड्डे	• 710 विमान • 136 हवाई अड्डे

उड़ान : हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक

आम नागरिकों की हवाई यात्रा का सपना पूरा करने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया

31 जनवरी 2022 तक

- 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति किराये पर 87 लाख लोगों ने की हवाई यात्रा
- 11 ऑपरेटरों ने 1.69 लाख उड़ानों का संचालन किया

415 मार्ग	66 हवाई अड्डे
8 हेलीपोर्ट	2 वाटर एयरोड्रोम

प्रौद्योगिकी-संचालित भारत

"डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के लिए दृढ़ता के साथ मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह उन लोगों को भी सिस्टम के साथ जोड़ रहा है, जिन्होंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी।"

- नरेन्द्र मोदी


Prayas

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

- **भारतनेट** के तहत मार्च 2022 तक 1.77 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार



ई-गवर्नेंस और सेवाओं की सुगमता

- डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने वाले 4.63 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर
- **रुपे कार्ड** के माध्यम से भारत के पहले वैश्विक भुगतान तंत्र में 70 करोड़ भारतीय शामिल।
- **उमंग ऐप** - 20,527 जन उपयोगी सेवायें, केंद्र एवं राज्य के 279 सरकारी विभागों और 33 राज्य स्तरीय एजेंसियों की 1417 सेवाएं शामिल
- **किसान रथ मोबाइल एप्लिकेशन** (कृषि उपज के परिवहन के लिए किराए पर वाहन लेने के लिए); 5.84 लाख किसान, किसान संगठन, व्यापारी और सेवा प्रदाता पंजीकृत

नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत **1,11,47,387 मानचित्रों** को डिजिटल किया गया। 93 प्रतिशत गांवों के भूमि अभिलेख कंप्यूटर में दर्ज
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत **3.56 करोड़** से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया



अंतरिक्ष एवं ड्रोन क्षेत्र- अनंत संभावनाएं

- प्रमुख उपलब्धियां- स्वदेश में निर्मित **रीयूसेबल लाँच वेहिकल – टेक्नोलोजी डेमोंसट्रेटर** (आरएलवी-टीडी) और मंगलयान का सफल प्रक्षेपण
- **अंतरिक्ष क्षेत्र** पहली बार **निजी भागीदारी** के लिए खुला
- **"व्योममित्र"** नामक पहली महिला ह्यूमनॉइड



सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण



"भाषा जो भी हो, हमारी संस्कृति भारतीय है"

- नरेन्द्र मोदी

भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि



स्टैच्यू ऑफ यूनिटी



बाबासाहेब स्मारक



जलियांवाला बाग स्मारक



जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित
जनजातीय गौरव दिवस

- स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों की स्वतंत्रता से जुड़ी भूमिका प्रदर्शित करने के लिए कोलकाता में बिप्लोबी भारत गैलरी की स्थापना
- सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का नई दिल्ली में निर्माण

शिल्पकृतियां/प्राचीन काल की धरोहरों को वापस लाना

- 2014 से अब तक प्राचीन काल की 228 अनमोल मूर्तियों को सफलतापूर्वक लाया गया

पर्यटन स्थलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

500 से ज्यादा गंतव्य केंद्र, 31 राज्य और 15 थीम आधारित सर्किट का विकास जारी

- बौद्ध सर्किट
- सागर तटीय सर्किट
- मरुस्थल सर्किट
- इको सर्किट
- हेरिटेज सर्किट
- हिमालय सर्किट
- कृष्ण सर्किट
- नॉर्थ-ईस्ट सर्किट
- रामायण सर्किट
- ग्रामीण सर्किट
- आध्यात्मिक सर्किट
- सूफी सर्किट
- तीर्थंकर सर्किट
- ट्राइबल सर्किट
- वाइल्ड लाइफ सर्किट

सांस्कृतिक स्थलों का विकास



अयोध्या



काशी विश्वनाथ कॉरिडोर



केदारनाथ धाम



सोमनाथ

पूर्वोत्तर
- एक विकास इंजन



"पूर्वोत्तर, भारत का नया विकास इंजन होगा।"

- नरेन्द्र मोदी

शांति और समृद्धि के लिए समझौते



पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

- पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) का बजट 2022-23 में ऐलान; 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन
- ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी और हथसिंगिमारी, नेमातिया और



कमलाबाड़ी एवं गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच रो-रो सेवा की शुरुआत।

- पूर्वोत्तर में 146.559 किमी की लंबाई की 121 सुरंगों का



निर्माण किया जा रहा है, वहीं 18.628 किमी की 25 सुरंगें परिचालन में हैं।

- असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल के पास बोगीबिल रेल-सह-सड़क पुल उत्तर और दक्षिण किनारों पर लिंक लाइनों (लंबाई-73 किमी) के साथ दिसंबर 2018 में पूरा हुआ- 5,920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत ।
- पूर्वोत्तर को आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है, स्कीम के तहत इंफाल-दीमापुर, शिलांग-कोलकाता; दीमापुर-गुवाहाटी, कोलकाता-लीलाबाड़ी; गुवाहाटी-लीलाबाड़ी; शिलांग-कोलकाता, आदि विभिन्न आरसीएस मार्ग शुरू।
- पूर्वोत्तर की कई जगहों जैसे तुइरियल, पारे और कामेंग में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण

पर्यावरण और सतत विकास

> विकास और पर्यावरण का संरक्षण प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। दोनों एक साथ हो सकते हैं और हम इस पर जोर दे रहे हैं
>
> - नरेन्द्र मोदी

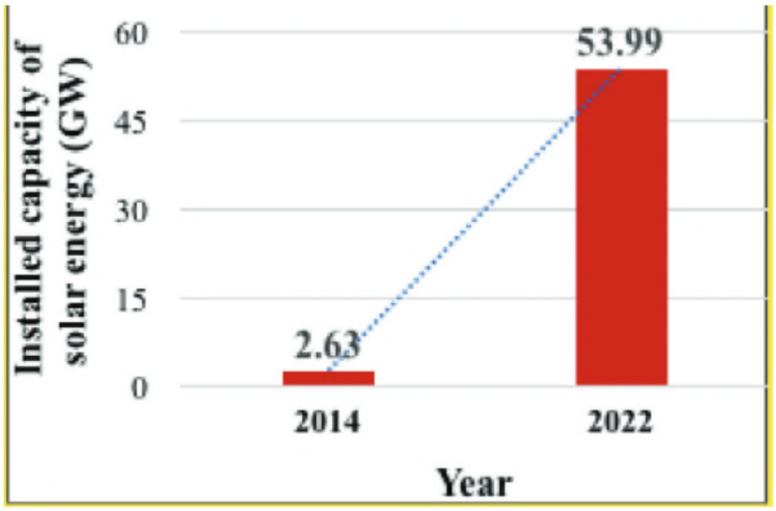


अक्षय ऊर्जा में भारी वृद्धि

- अक्षय ऊर्जा (आरई) की स्थापित क्षमता में पिछले साढ़े सात वर्षों में 286% की वृद्धि
- भारत अब स्थापित आरई क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है

- सौर ऊर्जा क्षमता 2014 से मार्च 2022 के बीच 2.6 गीगावॉट से बढ़कर 53 गीगावॉट से अधिक हुई, सौर पार्क योजना 20 गीगावॉट से दोगुना बढ़कर 40 गीगावॉट हुई। दरों में 1.99 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड निचला स्तर प्राप्त।
- 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में सहायता के लिए 15 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन किया गया शुरू

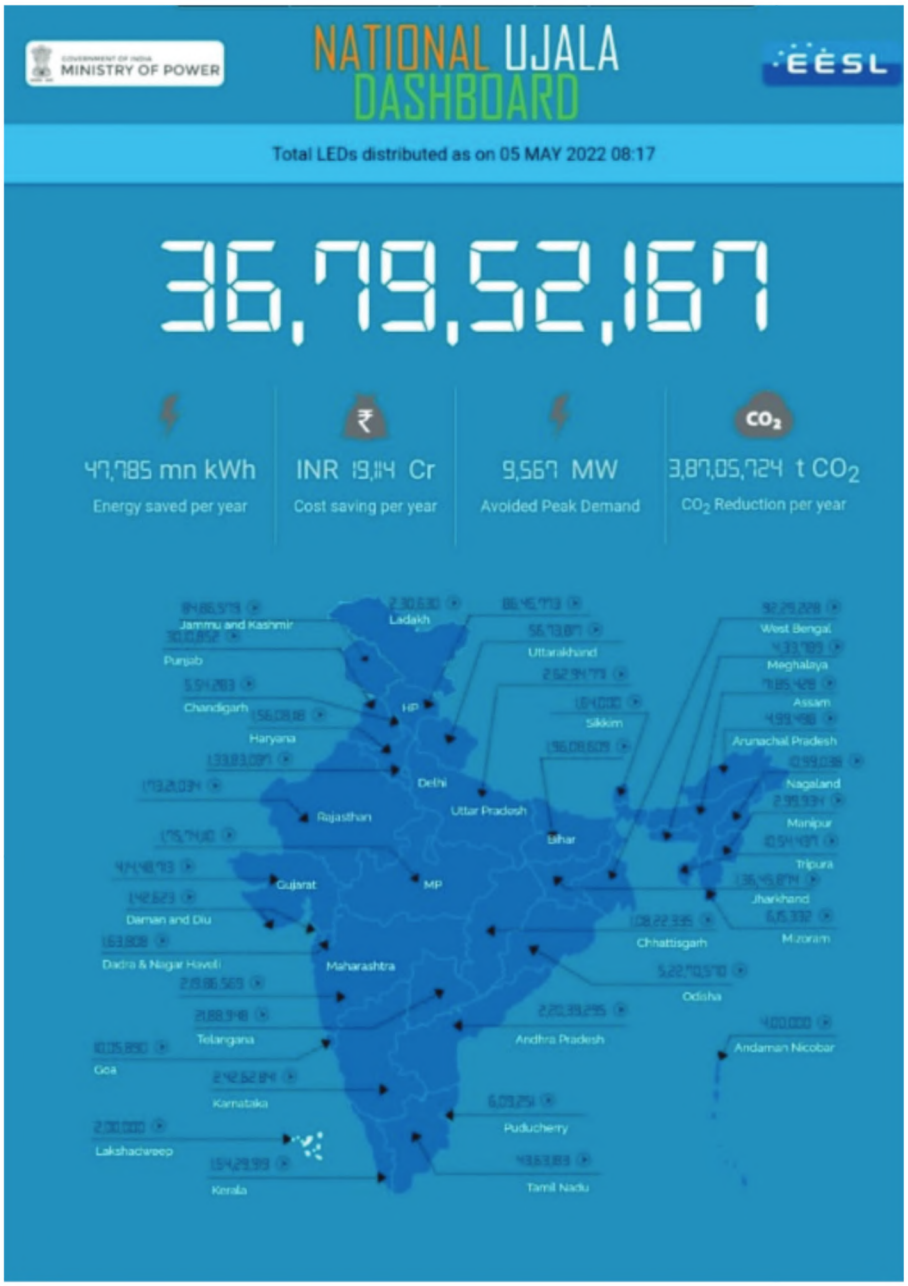
स्थापित सौर ऊर्जा में 18 गुना से अधिक की बढ़त (गीगावॉट में)



प्रधानमंत्री उन्नत ज्योति

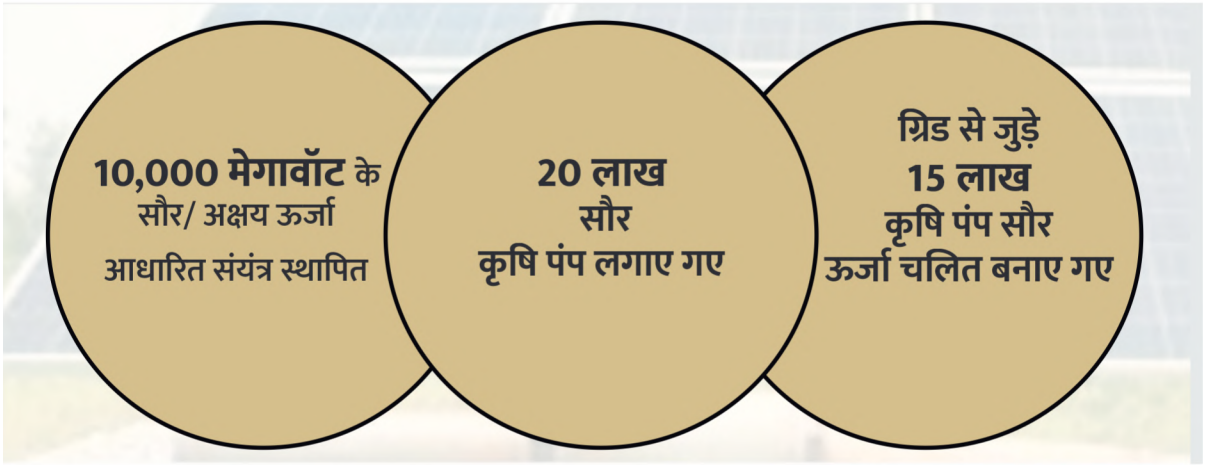
- सभी को सस्ती दरों पर एलईडी (उजाला) के उद्देश्य से 2015 में लॉन्च
- दुनिया का सबसे बड़ा गैर-सब्सिडी वाला स्वदेशी प्रकाश व्यवस्था का कार्यक्रम
- भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एलईडी बाजार है




MINISTRY OF POWER
NATIONAL UJALA DASHBOARD
EESL
Total LEDs distributed as on 05 MAY 2022 08:17
36,79,52,167
47,785 mn kWh
Energy saved per year
INR 19,114 Cr
Cost saving per year
9,567 MW
Avoided Peak Demand
3,87,05,724 t CO_2
CO_2 Reduction per year
Jammu and Kashmir
Ladakh
Punjab
Uttarakhand
Chandigarh
HP
Haryana
Sikkim
Delhi
Arunachal Pradesh
Nagaland
Rajasthan
Uttar Pradesh
Bihar
Manipur
Tripura
Gujarat
MP
Jharkhand
Daman and Diu
Chhattisgarh
Mizoram
Dadra & Nagar Haveli
Maharashtra
Odisha
Telangana
Andhra Pradesh
Andaman Nicobar
Goa
Karnataka
Puducherry
Lakshadweep
Kerala
Tamil Nadu

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना

- अन्नदाता को ऊर्जा दाता में बदलने के लिए फरवरी 2019 में प्रारंभ
- सौर ऊर्जा चलित कृषि पंप के माध्यम से 35 लाख से ज्यादा किसानों को ऊर्जा



एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड

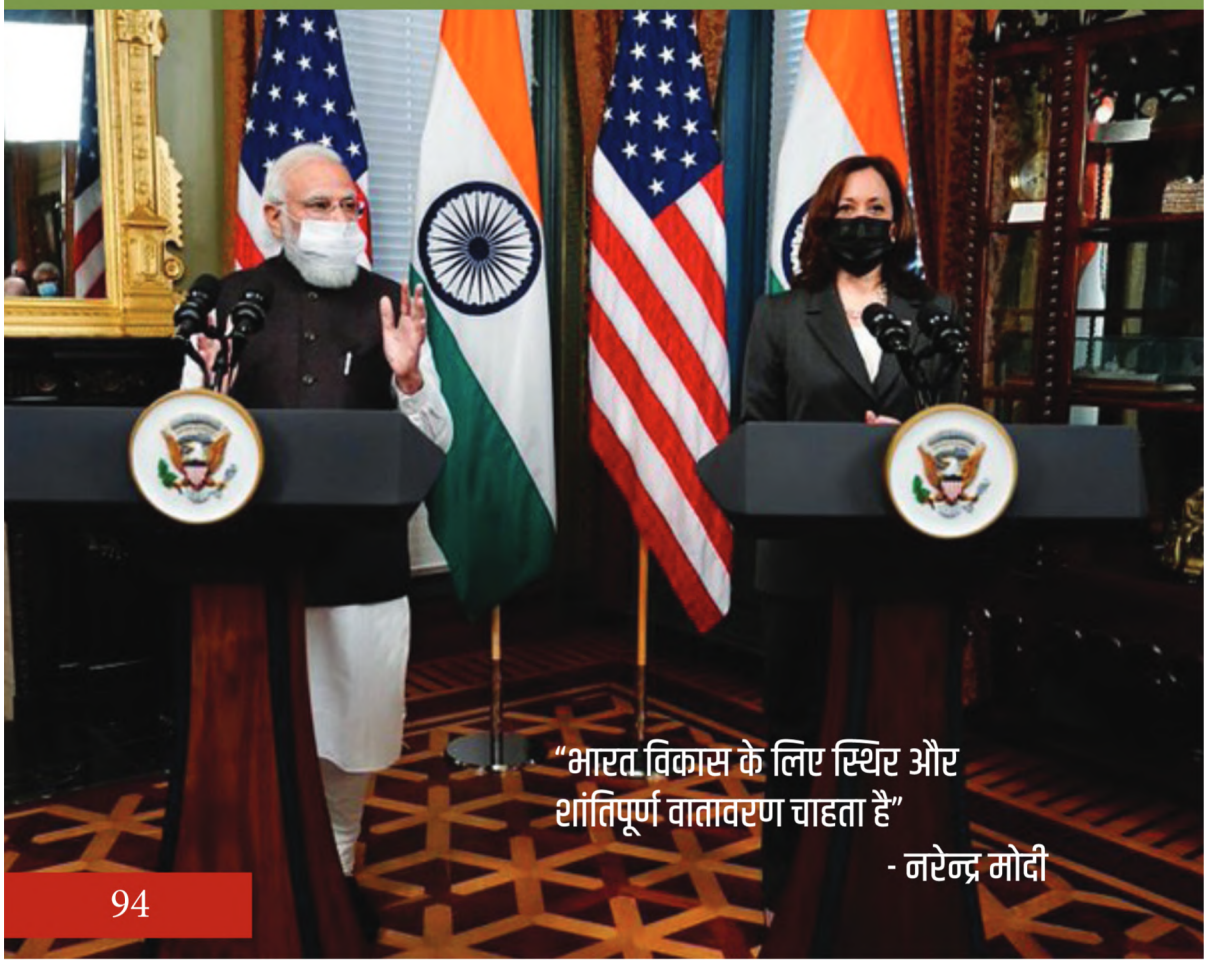
- भारत का 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में शुद्ध-शून्य उत्सर्जक बनने का संकल्प
- 108 देशों में सौर ऊर्जा तकनीकों को स्थापित करने के लिए नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत
- 31 मार्च 2022 तक स्थापित सौर क्षमता 53.99 गीगावॉट
- एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड की अवधारणा को साकार करने के लिए वैश्विक ग्रिड बनाने का प्रयास जारी

नमामि गंगे

- गंगा नदी का कायाकल्प करने, प्रदूषण में प्रभावी कमी लाने और संरक्षण के लिए 2014 में प्रारंभ
- अब तक 30,853 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 364 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है; 183 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है



राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति



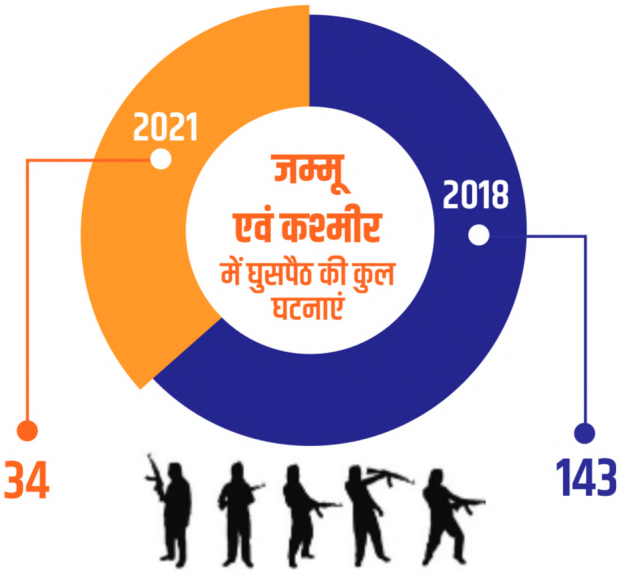
"भारत विकास के लिए स्थिर और शांतिपूर्ण वातावरण चाहता है"

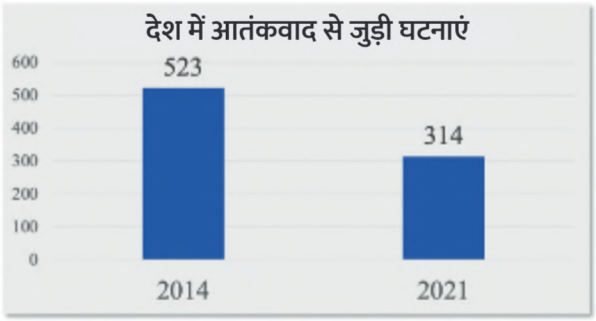
- नरेन्द्र मोदी

नागरिकों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना

देश में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं

2009	2021
3574	1723





उग्रवाद और नक्सलवाद

- एलडब्ल्यूई द्वारा हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी (2009 में 2 ,258 की तुलना में 2021 में 509)
- सिविलियन और सेक्योरिटी फोर्स की मौतों में 85 % की कमी (2010 में 1 005 की तुलना में 2 ,021 में 147)

पूर्वोत्तर में शांति संधियां

नागालैंड शांति संधि- 2015

नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एग्रीमेंट-2019

ब्रू-रियांग समझौता 2020

बोडो शांति संधि 2020

कार्बी आंगलोंग शांति समझौता- 2021

ऑपरेशन गंगा

- 22,500 भारतीयों को यूक्रेन से सफलतापूर्वक वापस लाया
- 18 देशों के 147 नागरिकों को भी बाहर निकाल
- 90 टन राहत सामग्री उपलब्ध कराई
- 90 उड़ानों का संचालन- 76 नागरिक 14 भारतीय वायु सेना के अभियान







आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण

- 890 केंद्रीय कानून लागू; 205 राज्य कानून रद्द किए गए; 130 राज्य कानून संशोधित और लागू; आरक्षण लाभ का विस्तार
- प्रधानमंत्री के विकास पैकेज का कार्यान्वयन तेज, 80,068 करोड़ रुपये की 63 परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी
- 28,400 करोड़ के परिव्यय के साथ नई औद्योगिक विकास योजना स्वीकृत
- औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 23,152 करोड़ रुपये के 456 एमओयू पर हस्ताक्षर

इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रमुख विकास

- स्मार्ट सिटी मिशन: 100 परियोजनाएं पूर्ण
- जल जीवन मिशन: 57% घरों को नल से जल
- पीएम जन आरोग्य योजना: 16.85 लाख लोग शामिल
- 5,300 किमी लंबी सड़क का निर्माण
- मनरेगा: 225 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार

सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक

- इन्सर्जन्सी के विरुद्ध अभियान, म्यांमार- 9 जून, 2015
- सर्जिकल स्ट्राइक, पीओके- 28-29 सितंबर, 2016
- बालाकोट हवाई हमला- 26 फरवरी 2019

विदेश नीति की उपलब्धियां

- क्वॉड और 2+2 वार्ता: अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत क्वाड समूह का अहम रणनीतिक साझेदार, हिंद-प्रशांत में महत्वपूर्ण भागीदारी; रूस के साथ 2+2 वार्ता की भी शुरुआत
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत चुना गया एक अस्थायी सदस्य
- भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की करेगा अध्यक्षता। 2023 में भारत में होगा जी -20 शिखर सम्मेलन



भारत सरकार

BOC\Hindi\May-2022

मुद्रक: पारस ऑफसैट प्रा. लि., नई दिल्ली